515

GENERAL STUDIES (Test–18)

निर्धारित समय: तीन घंटे *Time allowed: Three Hours*	**GSM (M-I)-2418**	*अधिकतम अंक: 250* *Maximum Marks: 250*

Name: Prem Singh **Mobile Number:** ______

Medium (English/Hindi): Hindi **Reg. Number:** ______

Center & Date: MN. 21/08/2024 **UPSC Roll No.** ***(If allotted)*:** 1132556

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

*इसमें **बीस** प्रश्न हैं तथा **हिन्दी** और **अंग्रेज़ी** दोनों में छपे हैं।*

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and **ENGLISH.***

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा भरा जाए *(To be filled by Evaluator only)*

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

मूल्यांकनकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Reviewer (Signature)

drishti | दृष्टि The Vision

Feedback

1. Context Proficiency (संदर्भ दक्षता)
2. Introduction Proficiency (परिचय दक्षता)
3. Content Proficiency (विषय-वस्तु दक्षता)
4. Language/Flow (भाषा/प्रवाह)
5. Conclusion Proficiency (निष्कर्ष दक्षता)
6. Presentation Proficiency (प्रस्तुति दक्षता)

drishti | दृष्टि The Vision

1. संसदीय उत्तरदायित्व के स्तर को निर्धारित करने में विपक्षी दलों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। चर्चा कीजिये।

(150 शब्द) 10

The role of opposition parties is critical in determining the level of parliamentary accountability. Discuss.

(150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारत ने ~~बि~~ ब्रिटिश संसदीय परम्परा के वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली को अपनाया है। जिसमें बहुमत वाले ~~[illegible]~~ दल की सरकार (लोकसभा) शासन करती है। संसदीय उत्तरदायित्व से आशय है कार्यपालिका का संसद के प्रति जवाबदेह होना।

संसदीय उत्तरदायित्व में कमी के कारण:
- पूर्ण बहुमत की सरकार
- कमजोर विपक्ष
- संसदीय सत्र की कम होती अवधि
- संसदीय चर्चा का कम समय
- गिलोटिन

विपक्षी दलों की भूमिका -

अनुच्छेद 75 के आधार पर कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति जवाबदेह होती है।

(1) जनता के मुद्दों को उठाकर - सदन में चर्चा, प्रस्ताव द्वारा

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

2. विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से

- अविश्वास प्रस्ताव - अनु- 75.
- ध्यानाकर्षण
- निंदा प्रस्ताव
- कटौती प्रस्ताव

③ विधेयकों को पारित होने से रोकने तथा चर्चा व परिचर्चा - विधेयक के बदलाव

④ प्रश्नप्रहर → तारांकित, प्रश्नकाल
अतारांकित, शून्यकाल

⑤ बजट पर चर्चा - तथा औचित्य पूर्ण प्रश्न

⑥ राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को गिराकर)

अतः विपक्ष संसदीय शासन में जनता की आवाज बनता है ब्रिटिश परम्परा में 'शैडो कैबिनेट' भी विपक्ष का प्रमुख हथियार होता है

drishti | दृष्टि The Vision

2. महिलाओं की श्रम बल भागीदारी को बढ़ाने में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10
Discuss the role of Self-Help Groups in widening women's labour force participation. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत में महिला श्रमबल भागीदारी निम्न बन रही है। PLFS सर्वे। जिससे जनसंख्या लाभांश का उचित लाभ हम नही उठा पा रहे है।

स्वयं सहायता समूह (SHG) की श्रमबल भागीदारी बढ़ाने में भूमिका ⇒

① महिला उद्यमिता की वृद्धि → महिला नेतृत्व की वृद्धि - कुटुम्बश्री केरल

② महिला जागरूकता व प्रशिक्षण ⇒ 'सेवा' (SEWA) के प्रयास

③ महिलाओं को उचित व संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना - FPO - रमादेवी के प्रयास राजस्थान बाड़मेर

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

(4) कुटीर उद्योगों का विकास — घरेलू उद्योग विकास

(5) महिला कौशल का विकास — हॉकी वाली सरपंच नीरू देवी — महिलाओं की तकनीकी शिक्षण व प्रशिक्षण

(6) महिला साक्षरता व परिवार नियोजन व कल्याण किया जाए)

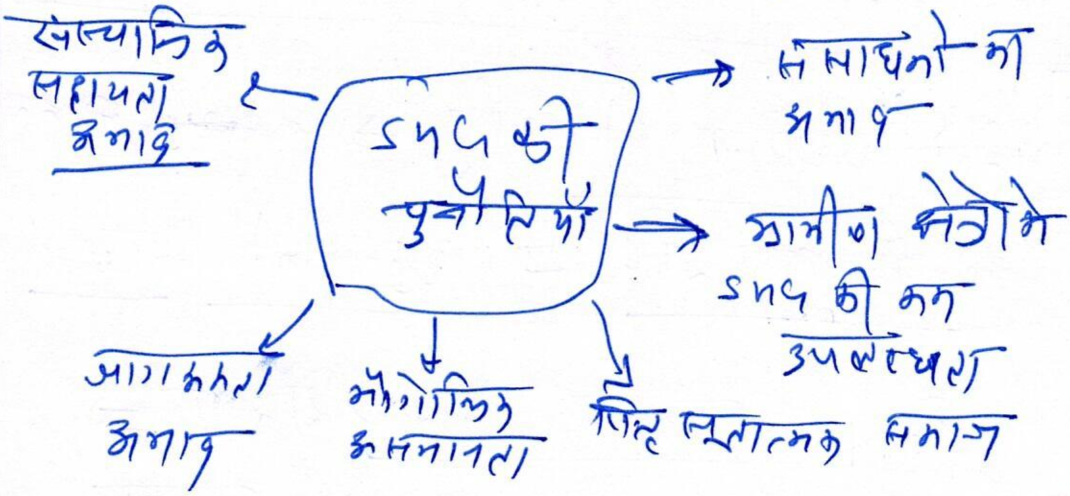

अतः महिला श्रम बल भागीदारी बढ़ाने हेतु सहकारी संस्थाओं, FPO व SHG द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के साथ मिलकर समन्वित प्रयास आवश्यक है

drishti | दृष्टि The Vision

3. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलने से समाज के कल्याण के प्रति समग्र दृष्टिकोण को बल मिला है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

The approach to welfare is wholesome and whole-of-society, with increasing private sector participation through Corporate Social Responsibility(CSR). Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के आधार पर वे उपक्रम जिनका कुल व्यापार 1000 करोड़ तथा नेटवर्थ 5 करोड़ या वार्षिक लाभ 5 करोड़ से अधिक है उन्हें औसत कुल लाभ का 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करना पड़ेगा।

CSR द्वारा समाज का कल्याण

① गांधी जी की ट्रस्टीशिप अवधारणा - समाज की संसाधन धारी।

② आधारभूत ढांचा का विकास - स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क -

उदा. - टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल, बूंद अभियान

③ सरकार पर वित्तीय भार में कमी।

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(4) अति पिछड़े क्षेत्रों के विकास के मौके - जनजातीय व पहाड़ी क्षेत्र

(5) पर्यावरण संरक्षण प्रयास - वृक्षारोपण, स्वच्छ पेयजल

(6) मानव विकास गतिविधियाँ - गरीबी निवारण व भुखमरी से सुरक्षा

(7) उद्योग व समुदाय दोनों को परस्पर लाभ

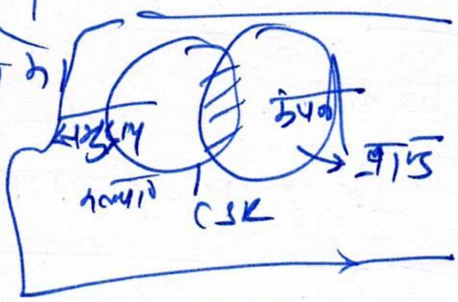

CSR की चुनौतियाँ

- CSR का व्यय कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित शिक्षा, पेयजल
- असमान वितरण महाराष्ट्र गुजरात
- कंपनियों द्वारा अतिरिक्त कर के रूप में लेना
- निश्चित व्यय प्रारूप नहीं

आगे की राह

सर्वांगीण विकास के साथ-साथ विकसित भारत के स्वप्न की प्राप्ति हेतु CSR का उचित विनियमन व निगरानी आवश्यक है।

4. व्यक्तिगत और राष्ट्रीय विकास के क्रम में मानसिक स्वास्थ्य, कम ध्यान दिये जाने वाला लेकिन प्रभावशाली चालक है। चर्चा कीजिये। इस संबंध में सरकार की सकारात्मक नीति क्या है? (150 शब्द) 10

Mental health is a less seen yet principally impactful driver of individual and national development. Discuss. What is the Government's positive policy momentum in this regard? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

मानसिक स्वास्थ्य आज की सबसे बड़ी समस्या है लैंसेट सर्वे के अनुसार आज शहरीकरण, मशीनीकरण, तकनीकी विकास ने मनुष्य को अकेला, चिड़चिड़ाहट व तनाव ग्रसित बना दिया है। प्रत्येक 5 में से 3 व्यक्ति मानसिक तनाव ले रहे है।

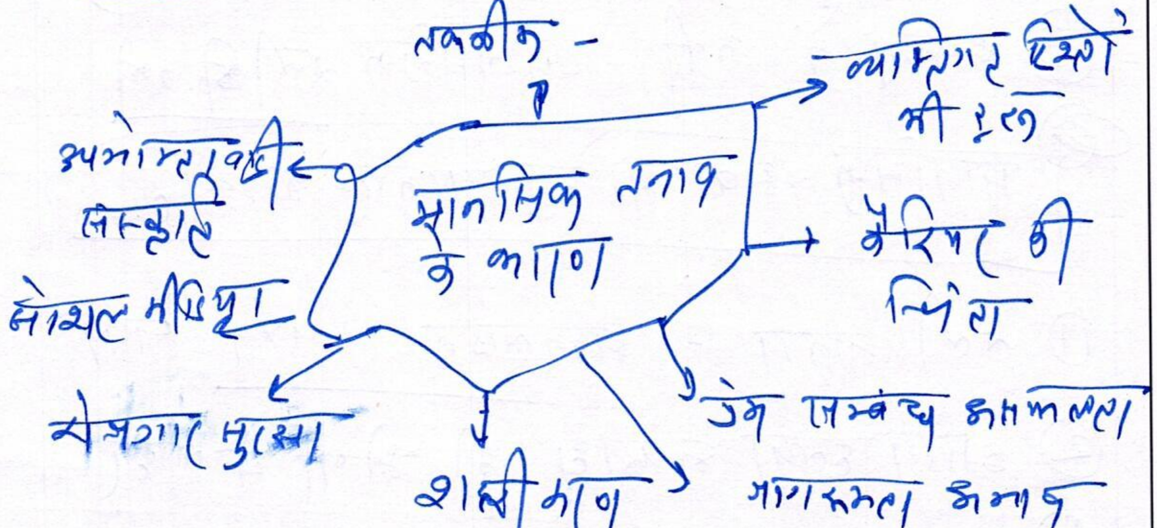

मानसिक स्वास्थ्य के व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव

1. तनाव - अकेलापन, अजनबीपन, आत्महत्या
2. आत्म विश्वास में कमी

drishti दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

③ रिश्तों की टूटन - तलाक, पारिवारिक विभाजन

④ बच्चों का पालन पोषण उचित नहीं।

राष्ट्रीय विकास पर मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव

① मानव संसाधन क्षमता में कमी - उत्पादकता

② अपराध वृद्धि - नशा, ड्रग्स, ~~घरेलू~~ हिंसा (NCRB)

③ क्षमता में कमी - सामाजिक पूंजी की कमी

मानसिक स्वास्थ्य हेतु सरकार की नीति

① टेली मानस - ऑनलाइन 24x7 सेवा

② आत्म हत्या अपराध की ~~श्रेणी~~ से बाहर

③ योगा व ध्यान को बढ़ावा - राज्य

④ जागरूकता - व अंधविश्वास के प्रति लोगों को जागरूक करना

मानसिक स्वास्थ्य हेतु केवल मानसिक चिकित्सकों की भर्ती के साथ-साथ हेल्पलाइन हेल्पडेस्क व पर्यावरण पर ध्यान भी आवश्यक है।

drishti | दृष्टि The Vision

5. ग्रामीण भारत के शासन में सुधार हेतु शुरू की गई विभिन्न डिजिटलीकरण पहलों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

Discuss the multiple digitization initiatives that have been unfolding in rural India to improve governance. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

ई-शासन प्रक्रिया में शासन-प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग बढ़ाया जाता है जिससे नागरिकों की सीधी भागीदारी बढ़ती है

ग्रामीण भारत के शासन सुधार हेतु डिजीटलीकरण पहलें →

(1) डिजीटल भारत अभियान - ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ना।

(2) ई-स्वामित्व :- जमीन के मालिकाना अधिकार तथा पट्टा वितरण।

(3) आयुष्मान भारत डिजीटल स्वास्थ्य मिशन - चिकित्सा सेवा

(4) टेलीमेडीसिन - ई-संजीवनी

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

पारदर्शिता हेतु → My gov.
- ↳ pmo की वेबसाइट
- ↳ P.M. आवास हेतु डिजीटल प्रार्थना पत्र

सब्सिडी व आर्थिक सहायता हेतु
- ↳ DBT - LPG - (पहल)
- ↳ उज्ज्वला योजना
- ↳ वित्तीय समावेशन - जन धन खाता
- ↳ आधार आधारित MGNREGA भुगतान
- ↳ JAM

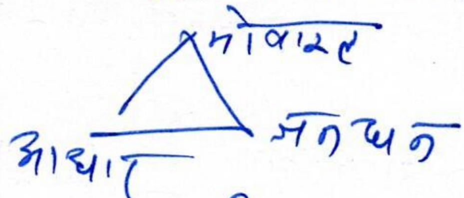

प्रशासन हेतु - जिला दर्पण, डिजी लाकर

ग्रामीण भारत में सुशासन स्थापना हेतु डिजीटल डिवाइड को समाप्त करने के साथ-साथ आधारभूत ढांचा का निर्माण आवश्यक है ताकि डिजीटलीकरण क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जा सके।

6. भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस लिखित संघीय संविधान को नम्यता (Flexibility) प्रदान करने का प्रयास किया गया है। विस्तारपूर्वक समझाइये। (150 शब्द) 10

A distinctive feature of the Indian Constitution is that it seeks to impart flexibility to a written federal Constitution. Elaborate. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान लिखित संविधान के के साथ-साथ नम्यता का मिश्रण है

अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया है।

① सामान्य बहुमत - राज्यों का नाम, सीमा

② विशेष बहुमत - मूल अधिकार

③ विशेष बहुमत व आधे राज्यों की अनुमति
↳ संघीय विषय

नम्यता प्रदान करने के कारण

① ~~[illegible]~~ संविधान भारतीय विविधता में एकता का परिचायक बन सका।

② विशाल भौगोलिक क्षेत्र

③ समय के साथ-साथ सकारात्मक

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

प्रथाओं को अपनाना।

(4) सहयोगी संघवाद को बढ़ावा

नम्य संविधान के लाभ व महत्व

(1) भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज़
└ संविधान संशोधन तथा न्यायिक व्याख्याएँ

(2) न्यायिक ~~समीक्षा~~ समीक्षा मूल संविधान का भाग - केशवानंद भारती वाद

(3) समाजवादी व कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक।

अर्थात् कठोर संविधान समय के साथ गतिरोध पैदा करते हैं तथा अत्यधिक नम्य संविधान अस्थिरता लाते हैं वहीं भारत की विशेष स्थिति इसे अद्वितीय संविधान बनाती है।

drishti | दृष्टि The Vision

7. न्यायिक कार्यों की पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता एक सुदृढ़ एवं प्रभावी विधिक प्रणाली की आधारशिला है, जिससे लोक विश्वास सुनिश्चित और न्यायिक सिद्धांत का कार्यान्वयन संपुष्ट होता है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

The transparency and accountability of judicial function form the cornerstone of a robust and effective legal system, ensuring public trust and upholding the principles of justice. Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

संविधान के अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका व विधायिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। अनुच्छेद 124 में भारत के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है।

पारदर्शिता व जवाबदेहिता सुदृढ़ व प्रभावी विधिक प्रणाली की आधारशिला

1. जनता का न्यायपालिका में विश्वास वृद्धि।

2. शक्तियों के पृथक्करण सिद्धान्त की अनुपालना।

3. सरकार व न्यायपालिका के मध्य न्यूनतम गतिरोध

(4) न्याय व्यवस्था में जवाबदेहिता

(5) समावेशी व क्षेत्रीय न्याय व्यवस्था

(6) मूल अधिकारों की रक्षा

(7) न्यायिक समीक्षा व सक्रियता व संयम में संतुलन

पारदर्शिता व जवाबदेहिता के अभाव से चुनौती

(1) गतिरोध — न्यायपालिका व विधायिका

(2) न्यायालय में विश्वास कमी - जजोक्रेसी

(3) न्याय एक पहुँच में कमी

(4) न्यायपालिका में भ्रष्टाचार

अतः एक संतुलित लोकतंत्र की स्थापना हेतु पारदर्शी व जवाबदेह न्यायपालिका आवश्यक है ताकि चेक एण्ड बैलेंस बना रहे।

8. राज्यों की राजनीतिक कार्यप्रणाली के संबंध में राज्यपालों के गैर-पक्षपातपूर्ण बने रहने से संबंधित संवैधानिक अवधारणा गहन जाँच के दायरे में है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

The constitutional conception of state governors occupying a non-partisan position with regard to the political functioning of states has come under severe strain. Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

पंजाब राज्य वाद (2023) में उच्चतम न्यायालय ने राज्यपालों को चुनी हुई सरकार के साथ मिलकर सहयोगात्मक रवैया अपनाने का आदेश दिया तथा राज्यपाल की क्रिया प्रणाली पर तंज कसा।

राज्यपाल ~~गहन~~ गैर-पक्षपातपूर्ण बने रहने की अवधारणा गहन जाँच के दायरे में क्यों?

① राज्यपाल व मुख्य मंत्री के मध्य टकराव
— की पश्चिम बंगाल मामला

② राज्य मंत्रिपरिषद के पारित विधेयकों पर कोई निर्णय न लेना —
तमिलनाडु मामला

③ मंत्रि परिषद के विधेयकों को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना
उदा - पंजाब मामला

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(ख) राज्य में राष्ट्रपति शासन की स्थापना: अनु- 356

(ग) राज्यों के दैनिक कार्यों में राज्यपाल का दखल।

सुझाव

(1) सरकारिया आयोग - राज्यपाल गैर राजनीतिक व्यक्ति।

(2) पुंछी आयोग - राज्यपाल की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से चर्चा

(3) संविधान की समीक्षा आयोग - राज्यपाल द्वारा संविधान के सिद्धांतों का पालन।

अतः राज्यपाल का पद का समय-समय पर समीक्षा की आवश्यकता रही है।

drishti | दृष्टि The Vision

9. "कारागार सुधार न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है, बल्कि एक विधिक एवं सामाजिक आवश्यकता भी है।" इस कथन के आलोक में भारत में कारागारों की स्थिति का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द) 10

"Prison reform is not just a moral imperative, but a legal and social necessity." In light of this statement, critically analyze the state of prisons in India. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय जेलों में आधारभूत सेवाओं तथा कैदी सुधार ~~के~~ ~~[illegible]~~ तंत्र की गंभीर सुधारों की आवश्यकता है

नैतिक अनिवार्यता कारागार सुधार

① मानवाधिकार सुरक्षा - क्षमता से अधिक कैदी

② 70% कैदी विचाराधीन - न्याय का अधिकार से वंचित

③ महिला सुरक्षा - जेलों मे महिला संबंधी हेल्प की कमी - महिला प्रशिक्षण केवल 13%

विधिक व सामाजिक आवश्यकता के रूप मे

① नागरिकों का मूल अधिकारों की

drishti
दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

रक्षा - अधिकतर क्षेत्र कमजोर वर्ग

(2) पैरोल व फरलो को अधिकार क्रियान्वयन है।

(3) जेल कल्याण - व्यवस्था में कमी है।

सुझाव

(1) पैरोल व फरलो प्रक्रिया - तकनीकि उपयोग - प्रभावी

(2) ओपन जेल मॉडल - राजस्थान

(3) मलिमथ समिति की अनुशंसाएं

अतः जेल कल्याणकारी राज्य के ओर एक सुधारात्मक उपागम होना सकती है।

drishti | दृष्टि The Vision

10. भारत में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए इसके कार्यान्वयन संबंधी प्रमुख मुद्दों एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालिये। (150 शब्द) 10

Discuss the need for an All-India Judicial Service (AIJS) in India, highlighting key issues and challenges in its implementation. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

चतुर्थ जजेज केस में उच्चतम न्यायालय के न्यायिक नियुक्ति आयोग की (NJAC) की स्थापना को असंवैधानिक करार दिया तभी से AIJS की आवश्यकता पर चर्चा जारी है

AIJS की आवश्यकता

(1) न्यायपालिका में न्यायाधीशों की पदों की रिक्ति - अधीनस्थ व जिला न्यायालय

(2) लंबित मामलों की भारी संख्या

(3) अधीनस्थ न्याय पालिका में राज्यवार असमानता - वेतन व भत्तों इत्यादि

(4) उच्च बुद्धिमता युक्त न्यायधीशों की नियुक्ति।

(5) आधारभूत अवसंरचना का अभाव

drishti | दृष्टि The Vision

कार्यान्वयन सम्बंधी मुद्दे व चुनौतियाँ

1. भाषा सम्बंधी चुनौती - स्थानीय समुदाय
2. आधारभूत अवसंरचना की भागीदारी
3. पर्याप्त प्रमोशन के अवसर नहीं
4. युवाओं में कैरियर हेतु मनोबल की कमी
5. राजनीतिक स्वच्छ/शक्ति की कमी

सुझाव

1. प्रशिक्षण के दौरान कैडर सम्बंधी भाषा का प्रशिक्षण व पेपर अनिवार्य
2. सूचना व तकनीकी का प्रयोग
3. अधीनस्थ न्यायपालिका का समय पर कैडर रिव्यू

अत AJES का गठन जहाँ न्यायधीशों के खाली पदों को भरेगा वहीं संघवाद की अवधारणा को भी मजबूत करेगा

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

drishti | दृष्टि The Vision

11. सराहनीय प्रयासों के बावजूद, भारत की जनजातीय जनसंख्या तक स्वास्थ्य सेवाओं के सफल वितरण में विभिन्न चुनौतियाँ विद्यमान हैं। विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

Despite commendable efforts, there are several obstacles that hinder the successful delivery of healthcare services to the tribal population of India. Analyse. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

NFHS-5 सर्वे के अनुसार 2/3 जनजातीय महिलाएं व बच्चे कुपोषण, एनीमिया तथा विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त है तथा मातृ व शिशु मृत्यु दर भी जनजातियों में सर्वाधिक है

जनजातीय स्वास्थ्य हेतु किये गये सरकारी प्रयास

- P.M पोषण अभियान
- जननी शिशु सुरक्षा योजना।
- सिकिल सेल एनीमिया निवारण
- आधारभूत ढांचा विकास
- PM आयुष्मान भारत मिशन
- सक्षम आंगनवाड़ी
- मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण
- पोलियो टीकाकरण
- PHC, CHC, जिला अस्पताल

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

जनजातियों क्षेत्रों में ~~[illegible]~~ स्वास्थ्य सेवा वितरण की चुनौतियाँ ⇒

1. निम्न आधारभूत सेवाएं - पेयजल, स्वच्छ -ता, तथा कनेक्टिविटी
2. चिकित्सकों की कमी - अधिकतर चिकित्सक शहरों में।
3. जागरूकता अभाव - अंधविश्वास व परम्परागत चिकित्सा पद्धतियाँ
4. निम्न मानव विकास - महिला स्वास्थ्य
5. अशिक्षा व गरीबी - अल्पपोषण
6. भ्रष्टाचार - सरकारी प्रयोजनाओं में संसाधनों का लीकेज
7. डिजीटल डिवाइड - टेली मेडीसिन की उपयोग नहीं।
8. जंगलागत प्रभावों की ओर अग्रसरित

drishti
दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

माना जाता है)

स्वास्थ्य सेवा वितरण सुधार हेतु सुझाव

1. मातृ भाषा में शिक्षा – चिकित्सकों हेतु
2. आधारभूत ढांचा विकास – सड़क, यातायात आंगनबाड़ी तथा स्वास्थ्य केंद्र
3. जागरूकता तथा परम्परा व आधुनिक चिकित्सा का समन्वित रूप।
4. गरीबी निवारण – खाद्यान्न सुरक्षा।
5. संस्थागत प्रसव – आशा व ग्राम पंचायतों को साथ लेकर।
6. सिविल सोसायटी, NGO व SHG के साथ मिलकर स्वास्थ्य सेवा वितरण सुधार।

अतः एक स्वस्थ व सशक्त भारत हेतु सभी लोगों का स्वास्थ्य होना जरूरी है तभी हम सतत विकास व उच्च मानव विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे।

drishti | दृष्टि The Vision

12. विधायी अंग के रूप में संसदीय कार्यों की गणना कीजिये। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि संसदीय संस्था और उसकी प्रक्रियाओं को प्रभावी बनाने हेतु सुधार एवं तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई अनिवार्य है? (250 शब्द) 15

Enumerate the functions of Parliament as the legislative organ. Do you agree that reforms and urgent remedial action seem imperative for making parliamentary institutions and processes effective?

(250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारत में सरकार के संघात्मक रूप के साथ-साथ संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें सरकार की शक्तियों का विभाजन कार्यपालिका, न्यायपालिका व विधायिका में किया गया है

विधायी अंग के रूप में संसदीय कार्य

1. विधि निर्माण → धन विधेयक (अनु-110)
   → वित्त विधेयक
   → सामान्य विधेयक

2. संविधान का संशोधन (अनु-368)

3. सरकार पर नियंत्रण → प्रस्ताव → अविश्वास
   → निंदा
   → प्रश्न पूछकर - लिखित व मौखिक
   → प्रश्न काल

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(4) मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण ⇒ सरकार को गिराकर – अविश्वास

(5) संसदीय विशेषाधिकार – अनु-105

(6) विधेयकों पर चर्चा, परिचर्चा, बहस व संशोधन करके

(7) समितियों के माध्यम से परिचर्चा

(8) सरकार की नीतियों की समीक्षा।

संसदीय संस्था व उसकी प्रभाविता में कमी

(1) विलोपित की बढ़ती प्रवृत्ति – ADR

(2) संसदीय चर्चा/परिचर्चा के समय में निरन्तर कमी

(3) संसदीय समितियों के पास विधेयकों का नहीं भेजा जाना – केवल 14%

(4) धन विधेयक के रूप में विधि पारित कराना ⇒ आधार सम्बन्धी विधेयक

drishti | दृष्टि The Vision

(5) राजनीति का अपराधीकरण = 40%
सांसदों पर आपराधिक मुकदमे – ADR

(6) महिला नेतृत्व में कमी – 2019 के 78 के मुकाबले 2024 में 73 महिला सांसद

उपचारात्मक कार्यवाही

(1) चर्चा, परिचर्चा व बहस संस्कृति का विकास

(2) विधेयकों का संसदीय समितियों में उचित चर्चा

(3) लोक सभा अध्यक्ष का निर्णय – धन विधेयक के सम्बंध

(4) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में सुधार

(5) नारी शक्ति वंदन अधिनियम का तुरन्त क्रियान्वयन

अतः एक सशक्त लोकतंत्र के निर्माण हेतु जिम्मेदार विपक्ष व जवाबदेह सत्ता पक्ष दोनों ही जरूरी है तथा सरकारात्मक संसदीय धाराओं का अनुपालन आवश्यक है

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

drishti | दृष्टि The Vision

13. वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र कम विरोधाभासी होने के साथ विवादों को सुलझाने के पारंपरिक तरीकों का बेहतर विकल्प प्रदान कर सकते हैं। चर्चा कीजिये। इस दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गए हैं? (250 शब्द) 15

Alternate Dispute Resolution mechanisms are less adversarial and can provide a better substitute to the conventional methods of resolving disputes. Discuss. What are the government's efforts to bring out a transformative shift towards it? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र (ADR) विवाद सुलझाने के लिए पारम्परिक न्यायालय से इतर प्रणाली है। इसमें दोनो पक्ष किसी एक मध्यस्थ के माध्यम से विवाद का निपटारा करते हैं।

वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र
→ लोक अदालत
→ माध्यस्थ तंत्र
→ मध्यस्थम
→ ट्रिब्यूनल

वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के लाभ

① सस्ता व व्यवहार्य विकल्प

② न्याय लयों पर ~~न्या~~ लंबित मुकदमों के भार को कम करता है।
SC में 80,000 केस लंबित

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(3) तीव्र निपटान – फास्ट ट्रैक सेटलमेंट

(4) किसी भी पक्ष को हारने व जीतने की भावना नहीं।

(5) संस्थानों की निष्पक्षता

(6) संसाधनों की कम आवश्यकता तथा वहनीय न्याय

(7) परम्परागत ग्राम न्याय तंत्र की भावना पर आधारित

वैकल्पिक विवाद समाधान की चुनौतियाँ

(1) मध्यस्थ केन्द्रों का अभाव

(2) जागरूकता का अभाव – नागरिकों में

(3) दक्ष व प्रशिक्षित मध्यस्थ प्रोफेशनल्स की कमी।

(4) विवादों की लंबित होने की

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

पुरानी परम्परा

सुझाव
→ वैकल्पिक समाधान तंत्र हेतु जागरूकता।
→ लोक अदालतों की क्षमता वृद्धि
→ तुलनात्मक तकनीक विकास
↓ मध्यस्थता केन्द्र स्थापन (सिंगापुर की तर्ज) पर

सरकार द्वारा किये गये प्रयास

1. लोक अदालत - नालसा (अनु 39(A))
2. ग्राम न्यायालय की स्थापना
3. अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता तंत्र की स्थापना
4. मध्यस्थता कर्मियों को प्रशिक्षण
5. ई-सुनवाई - वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर गवाही
6. न्याय आपके द्वार पहल
7. पुराने कानूनों की समाप्ति

न्याय न केवल समय पर होना आवश्यक है बल्कि वह वहनीय, तुरन्त, निष्पक्ष-न्याय होता हुआ दिखना भी आवश्यक है

drishti | दृष्टि The Vision

14. दिल्ली के शासन और भारत के संघीय ढाँचे पर इसके संभावित प्रभाव पर विचार करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन (GNCTD) (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

(250 शब्द) 15

Critically examine the provisions of the Government of National Capital Territory of Delhi (GNCTD) (Amendment) Act, 2023 considering its potential impact on the governance of Delhi and the federal structure of India. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

~~संविधान~~ अनुच्छेद 239AA के माध्यम से दिल्ली को विशेष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। यद्यपि चुनी हुई सरकार के साथ-साथ उपराज्यपाल होगा और दैनिक प्रशासन में सरकार की मदद करेगा।

GNCTD 2023 (संशोधन) विधेयक के प्रमुख प्रावधान ⇒

(1) उपराज्यपाल सरकार की सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं।

(2) ~~उपराज्यपाल~~ राज्य मामलों ~~के~~ हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति जिसमें मुख्य मंत्री शामिल और अन्य अधिकारियों के स्थानान्तरण व पोस्टिंग

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

हेतु सलाह देगी।

③ उपराज्यपाल मंत्रि सलाह को मानने हेतु बाध्य नहीं।

④ पुलिस, जमीन का सभी शक्तियां उपराज्यपाल के पास।

GNCTD (संशोधन) अधिनियम 2023 की आलोचना ⇒

① संसदीय प्रतिरूप का विरोधी धारणा।

② 'चुनी हुई सरकार की नागरिकों के प्रति जवाबदेही प्रभावित।

③ उपराज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है अतः वह स्वयं अलोकतांत्रिक प्रतिनिधि

④ मंत्रिपरिषद व मुख्यमंत्री की

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

शक्तियों में कमी।

(5) राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के बीच विवाद की स्थिति।

सुझाव

(1) मध्यम मार्ग का पालन करते हुए संघीय लोकतंत्र की स्थापना

(2) उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन।

(3) सभी हितधारकों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना।

अतः दिल्ली के नागरिकों के समग्र विकास व सेवा प्रदायगी को सुनिश्चित करने हेतु दोनों पक्षों का सहयोगात्मक नजरिया जरूरी है।

drishti | दृष्टि The Vision

15. भारतीय लोकसभा और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में अध्यक्ष की भूमिका की तुलना कीजिये। चर्चा कीजिये कि ये भूमिकाएँ अपने-अपने विधायी निकायों की कार्यप्रणाली को कैसे प्रभावित करती हैं। (250 शब्द) 15

Compare and contrast the role of speaker in the Indian Lok Sabha and British House of Commons . Discuss how these roles impact the functioning of their respective legislative bodies. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत व ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स दोनों ही संसदीय शासन प्रणाली के आधार स्तम्भ है

भारतीय लोक सभा व ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स अध्यक्ष में समानताएं

(1) दोनों का चुनाव निम्न सदन से

(2) विधेयकों के पारित होने पर उन्हें धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करना

(3) सदन के नियमों का संचालन तथा सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(5) दोनों मतदान में भाग लेते हैं

भिन्नताएं

भारतीय लोक सभा अध्यक्ष	ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स अध्यक्ष
(1) अध्यक्ष बनने के बाद भी राजनीतिक दल का सदस्य	(1) अपने दल की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा
(2) दल-बदल की स्थिति में निर्णय-निरर्हता का	→ ऐसी कोई शक्ति नहीं है
(3) दलीय भावना अधिक	(3) दलगत राजनीति से दूर रहता
(4) शक्तियाँ संविधान, सदन के नियम व कानून की व्याख्या	(4) सदन के नियमों से शक्ति ग्रहण करता

drishti
दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

विधायी निकायों की कार्य प्रणाली पर प्रभाव

विधिक अध्यक्ष

1. सदन में विधि की नैतिक व्याख्याकार
2. सदन में अनुशासन बनाये रखना
3. सदस्यों के विशेषाधिकार सुरक्षा

लोक सभा अध्यक्ष

1. गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना व निर्णायक मत देना।
2. दल-बदल सम्बन्धी निर्णय
3. संसदीय परम्परा का विकास

अतः सदन का अध्यक्ष संसदीय लोकतंत्र परम्परा में एक न्यायाधीश से लेकर संरक्षक की भूमिका अदा करता है।

16. राजकोषीय संघवाद सुनिश्चित करने एवं केंद्र और राज्य सरकारों की राजकोषीय शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने में वित्त आयोग की महत्त्वपूर्ण भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द) 15

Critically evaluate Finance Commission's crucial role in ensuring fiscal federalism and maintaining a balance between the fiscal powers of the central and state governments. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 के तहत प्रति 5 वर्षों मे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है

वित्त आयोग के उद्देश्य
- → कर सुधार
- → करो का वितरण तथा राज्य का हिस्सा
- → राजकोषीय संघवाद की सुरक्षा व सुदृढ़ता

राजकोषीय संघवाद व केंद्र राज्यों के मध्य वित्तीय शक्तियों के संतुलन मे भूमिका

① करो का उचित वितरण – अनु 269 – केंद्र द्वारा उगाहे जाने वाले कर व राज्यों को वितरण

drishti | दृष्टि The Vision

(2) केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा

(3) पंचायती राज संस्थाओं को वित्त का वितरण

(4) राज्यों के मध्य करों के वितरण का फार्मूला तय करना। ताकि संघवाद सुदृढ़ हो सके।

(5) राज्यों के बढ़ते लोन की जीन शर्तों की स्थापना।

(6) केंद्र द्वारा दी जाने वाले अनुदानों का वितरण व अनुशंसा करना।

वित्त आयोग की असफलता

(1) 15वें वित्त आयोग राज्यों का ... करना

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(2) करों के राज्यों के मध्य वितरण का उत्तर व दक्षिणी राज्यों में प्रतिरोध

(3) अनुशंसाएं अनिवार्य नहीं होती।

अतः वित्त आयोग न केवल राजकोषीय संघवाद को मजबूत करता है बल्कि प्रतिस्पर्धी व सहयोगी संघवाद की स्थापना भी करता है।

17. क्या भारत ने अपनी वैश्विक स्थिति और प्रभाव को बढ़ाने के लिये अपनी सॉफ्ट पावर का लाभ उठाया है? विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

Has India leveraged its soft power to enhance its global stature and influence? Analyze. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

सॉफ्ट पावर किसी देश की वह शक्ति होती है जिसमें परम्पराओं, संस्कृति व सिद्धान्तों के माध्यम से अपना प्रभाव बढ़ाया जाता है एवं विदेशी नागरिकों द्वारा किसी देश के मूल्यों का आत्मसात किया जाता है

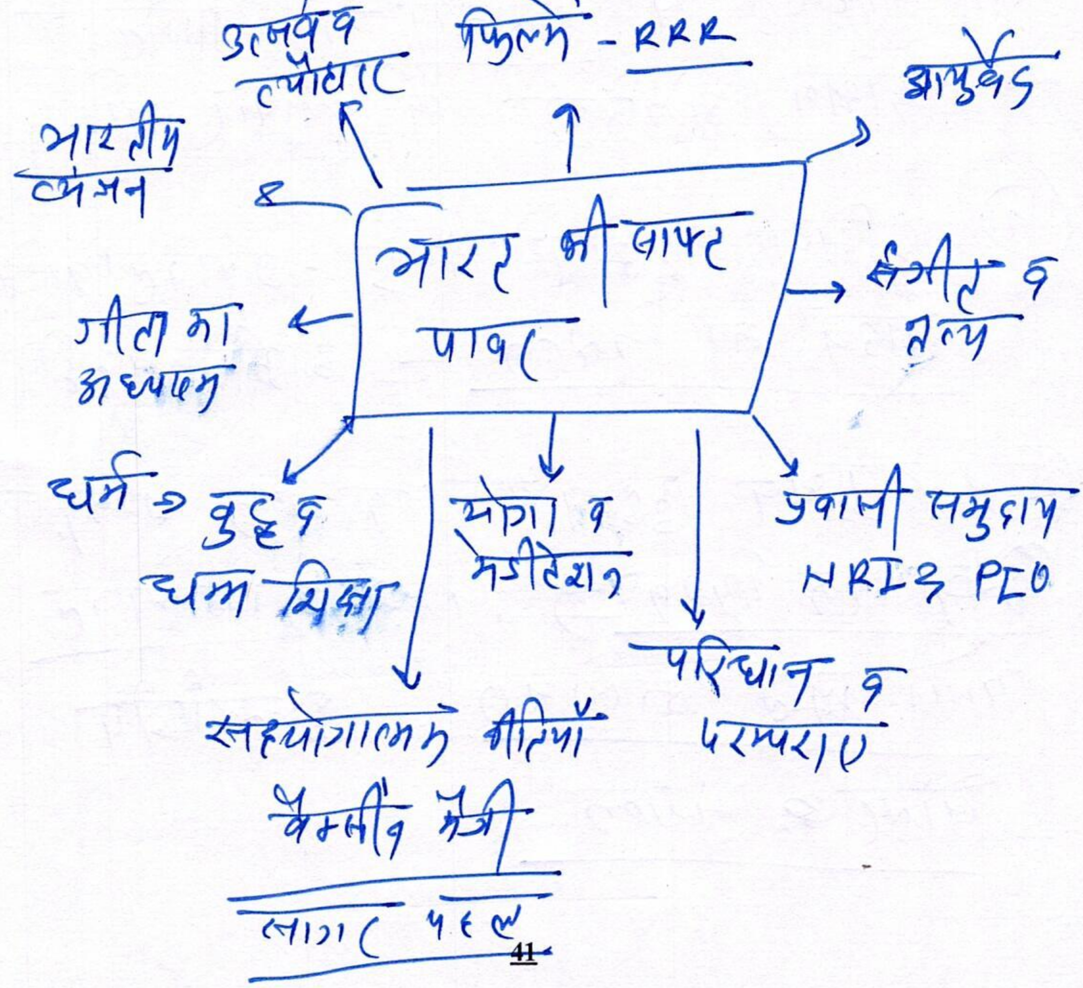

drishti | दृष्टि The Vision

वैश्विक स्थिति और प्रभाव बढ़ाने में सॉफ्टपावर का लाभ ⇒

① योगा - 21 June - अन्तर्राष्ट्रीय योगा दिवस

② अनिवासी भारतीय → अमेरिका से सिविल न्यूक्लियर समझौता
→ आस्ट्रेलिया 2+2 संवाद

③ कैरेबियन देशों में गिरमिटियों के माध्यम से मराकेश में शामिल व दक्षिण अमेरिका से व्यापार वृद्धि।

④ दक्षिण - दक्षिण संवाद - ग्लोबल वैश्विक साउथ का नेतृत्व = अफ्रीकी महाद्वीप

⑤ वसुधैव कुटुम्बकम व एक पृथ्वी, एक विश्व एक विश्व ⇒ G20 में ग्लोबल बायो फ्यूल अलायन्स, अन्तर्राष्ट्रीय सोलर संगठन

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(6) बुद्ध व रामायण के प्राचीन इतिहास

लुक ईस्ट नीति – इंडो पैसिफिक क्षेत्र

(7) महत्वपूर्ण में वालीवुड फिल्मों ने भारत के प्रति रुचि को सहयोगी बनाया

(8) निवेश में वृद्धि – मारीशस

(9) यूरोपीय यूनियन के साथ सहयोगात्मक जनमत।

(10) UNO में भागीदारी · शांति मिशन

सॉफ्ट पावर हेतु चुनौतियाँ
→ BRI परियोजना
→ आर्थिक वाद
→ साम्प्रदायिकता - हिंसा
↓ वैश्विक घटना क्रम - रूस-यूक्रेन, इजराइल-फिलिस्तीन,
↓ संरक्षणवादी नीतियाँ
↓ निवेश में कमी

आगे की राह – भारत को वैश्विक नेतृत्व में अग्रिम स्थान हेतु सॉफ्ट पावर का हार्ड पावर के साथ मिश्रण करके स्मार्ट नीति अपनानी जरूरी है साथ ही तीव्र आर्थिक विकास व समृद्धि की राह पकड़नी होगी।

drishti | दृष्टि The Vision

18. अपनी स्थापना के बाद से पिछले दो दशकों से अधिक समय में, बिम्सटेक (BIMSTEC) ने अपनी विशाल क्षमता का उपयोग करते हुए सामूहिक उन्नति की दृष्टि वाले समूह के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने में एक लंबा सफर तय किया है। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द) 15

In the past more than two decades since its establishment, BIMSTEC has come a long way in distinguishing itself as a group with a vision for collective advancement utilizing its vast potential. Comment. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

बिम्सटेक (BIMSTEC) ⇒ बंगाल की खाड़ी के तटीय देशों का संगठन है। जिसमें दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश शामिल है। सदस्यों में भारत, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया प्रमुख है।

बिम्सटेक का महत्व

① आर्थिक एकीकरण में सहायक — सार्क की कमियों को पूरा करना।

② बंगाल खाड़ी क्षेत्र में व्यापार निर्यात में सहयोगात्मक नीतियाँ

③ भारत पूर्व- इंडो पेसिफिक क्षेत्र की

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

स्थापना हेतु निम्न सक्रियता

(4) प्राकृतिक आपदा में सहायता - सागर पहल

(5) क्षेत्रीय कनेक्टिविटी व आधारभूत ढाँचा का विकास - BBIN व IMT गलियारा

(6) अर्थव्यवस्थाओं का अधिक खुलापन व टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियरों को कम करना।

विम्सटेक की चुनौतियाँ

(1) चीन का बढ़ता प्रभुत्व → BRI प्रोजेक्ट
↳ String of Pearls नीति

(2) आर्थिक व्यापार बहुत कम - सबसे कम संगठित क्षेत्र

(3) क्षेत्रीय अस्थिरता < म्यांमार - सैन्य शासन
बांग्लादेश - हसीना सरकार अपदस्थ

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(4) चीन पर बढ़ती निर्भरता – FTA की अनुपस्थिति तथा भारत का बढ़ता व्यापार घाटा

(5) दक्षिणी चीन सागर विवाद

(6) चीन की ऋण जाल की नीतियाँ – श्रीलंका

सुझाव

(1) बिम्सटेक का प्रयोग एक क्षेत्रीय सहयोगी संगठन के रूप में करना

(2) अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण – FTA

(3) लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना

(4) कनेक्टिविटी योजनाओं को तीव्र विकास व समय पर पूरा करना – IMT

(5) गैर-संगठित व संगठित ~~व्यापार~~ अपराधपर नियंत्रण

(6) ड्रग व्यापार पर नियंत्रण

अतः बिम्सटेक का उपयोग भारत अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी के विंग के रूप में कर सकता है जिससे भारत के महत्व में वृद्धि होगी।

drishti | दृष्टि The Vision

19. उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते वैश्विक ऋण संकट के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पड़ने वाले प्रमुख परिणामों का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

Examine the major outcomes of soaring global debt crisis in emerging and developing economies on international relations. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

हाल के समय में उभरती व विकासशील अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक ऋण जाल के संकट का सामना कर रही है जैसे- श्रीलंका, जिबूती, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव इत्यादि

ऋण जाल वह नीति है जिसके अस्पष्ट शर्तों के आधार पर बड़े बड़े ऋण दिये जाते बाद में ऋण लेने वाला देश ऋण अदायगी में असफल हो जाता है

वैश्विक ऋण संकट के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंधों पर प्रभाव ⇒

(1) संप्रभुता में कमी — IMF, विश्व बैंक द्वारा ऋणी देश पर मनमानी शर्तों को थोपना - उदा० पाकिस्तान

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(2) नवीन वित्तीय उपनिवेशवाद :→ चीनी मछली जाल नीति मछली देश के क्षेत्रों पर अधिकार कर लेती है तथा संसाधनों का अपने हित हेतु शोषण करती है —
उदा॰ श्रीलंका : हम्बनतोता बंदरगाह
पाकिस्तान - ग्वादर बंदरगाह

(3) वैश्विक शांति हेतु खतरा ⇒ आतंकवाद व अलगाववाद का उदय → संसाधनों की लूट

(4) संरक्षणवादी नीतियों का प्रसार जिससे विवैश्वीकरण की प्रक्रिया तथा व्यापार युद्ध का प्रसार

(5) अशांति पैदा करने वाले तत्वों का उदय तथा चुनी हुई सरकारों का गिरना
उदा॰ कोलंबिया विद्रोह

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

⑥ पर्यावरण प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन सम्बंधी पहलों को इतना तथा समानता आधारित संगठन कमजोर होते है।

⑦ बहुपक्षीय विश्व का उदय – आसियान, ब्रिक्स, SCO आदि।

⑧ वैश्विक बैंकों की आलोचना तथा गरीबी का प्रसार।

अत: गहन सहा लिमट के समाधान हेतु सतत विकास लक्ष्यों व समावेशी विकास पर ध्यान देते हुए वैश्विक सहा प्रक्रिया को अधिक उदार बनाया जाना आवश्यक है। साथ ही कमजोर देशों की क्षमता निर्माण पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है।

drishti | दृष्टि The Vision

20. यूरोप का हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर बढ़ता ध्यान तथा भारत के साथ गहराता आर्थिक और तकनीकी सहयोग परस्पर लाभ प्रदान करता है। चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Europe's increased focus on the Indo-Pacific and the deepening economic and technological collaboration with India offer mutual benefits. Discuss. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

हिन्द प्रशान्त क्षेत्र में भूक से ही वैश्विक समुदाय का हित रहे हैं तथा वैश्विक व्यापार का 60% हिन्द प्रशान्त से होकर जाता है। हाल ही में क्वैड तथा ऑकस जैसे संगठनों ने हिन्दप्रशान्त यूरोप के महत्व को प्रतिपादित करता है।

हिन्द प्रशान्त में भारत का महत्व

① समग्र सुरक्षा प्रदाता ~ सागर

② चीन के प्रति प्रमुख क्षेत्रीयशक्ति

③ पारम्परिक प्रतिस्पर्धा व आर्थिक महत्व

④ विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

यूरोप के साथ सम्बंधों पर भारत के लाभ

1. भारतीय निर्यात हेतु प्रमुख गन्तव्य - यूरोपीयन यूनियन व्यापार अधिशेष भारत के पक्ष में
2. UNSC में स्थायी सदस्यता का समर्थन - फ्रांस व UK
3. पर्यावरण संकट व जलवायु परिवर्तन
4. भारतीय डेयरी उत्पादों हेतु बाजार
5. सौलर तकनीक तथा छोटे परमाणु रिएक्टरों हेतु सहयोग
6. रक्षा हथियार आयात - फ्रांस
6. शिक्षा का क्षेत्र -

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

यूरोप को लाभ

① हिन्द प्रशान्त में शांति - चीन के बढ़ते वर्चस्व को चुनौती

② भारत का बढ़ता निवेश - टाटा कंपनी जगुआर -

③ अंतरिक्षीय सहयोग (अर्टेमिस), बायोफ्यूल अलायंस

④ IMEC - कॉरिडोर - मध्यपूर्व से होकर BRI प्रोजेक्ट की चुनौती का सामना

चिन्ता के क्षेत्र

① भारतीय निर्यात पर नॉन टैरिफ बाधाएं

② CABM - कार्बन उत्सर्जन टैक्स

③ आतंकवाद - अलगाववादी ताकतें

अतः शांतिपूर्ण विश्व हेतु यूरोप व भारत को मिलकर और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

drishti | दृष्टि The Vision

Space for Rough Work

(रफ कार्य के लिये स्थान)

Space for Rough Work

(रफ कार्य के लिये स्थान)

Space for Rough Work

(रफ कार्य के लिये स्थान)

Space for Rough Work

(रफ कार्य के लिये स्थान)